दृष्टि The Vision

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

(6 पुस्तकों की शृंखला की पहली कड़ी)

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC-NTA NET में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले 1600+ प्रश्नों व उनकी व्याख्याओं का संकलन

1600+ अभ्यास प्रश्न (व्याख्या सहित)

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियो,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उड़ान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खूब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वो सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का भारी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नहीं है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी माँग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQs पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज

Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि
The Vision

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC-NTA NET में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले 1600+ प्रश्नों व उनकी व्याख्याओं का संकलन

Drishti Publications
dp

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण- मार्च 2020

मूल्य : ₹ 280

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशंस, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

आप सबने यह प्रसिद्ध उक्ति सुनी ही होगी कि हम अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाते हैं युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। लगभग ऐसी ही बात 'सुन त्ज़ू' (Sun Tzu) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द आर्ट ऑफ वॉर' में भी कहते हैं–"विजेता योद्धा पहले जीतते हैं फिर युद्ध के मैदान में जाते हैं जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध लड़ते हैं और फिर जीतने की इच्छा रखते हैं।" इन दोनों ही कथनों का मूल भाव यह है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिये कुशल रणनीति तथा उसी अनुरूप कठोर अभ्यास अनिवार्य हैं। इसके अभाव में हम बस रेस का हिस्सा होते हैं जीत के दावेदार नहीं। और सिविल सेवा परीक्षा भी इस नियम का अपवाद नहीं है। खासकर अगर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ प्रतिस्पर्द्धा अधिक सघन है इसलिये तैयारी भी इसी अनुरूप करनी होगी। इसी सिलसिले में हम 'प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़' के नाम में एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी के रूप में 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' का प्रकाशन किया जा रहा है। हम आगे इस सीरीज़ और प्रस्तुत पुस्तक के विषय-वस्तु की चर्चा करेंगे, इसके पहले भारतीय राजव्यवस्था को तैयार करने की रणनीति पर थोड़ी नज़र डालते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नपत्र को देखें तो भारतीय राजव्यवस्था से लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछने का चलन रहा है। इस प्रकार यह कुल प्रश्नों का लगभग 20% हिस्सा धारण करता है। अब अगर इन्हीं वर्षों के प्रिलिम्स कट ऑफ को देखें तो यह औसतन कुल अंकों के 50% के आस-पास रहा है। अर्थात् 200 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिये कभी 100 से कुछ अधिक तो कभी 100 से कुछ कम अंकों की आवश्यकता होती है। अगर हम 110 का भी औसत मान लें तो सारी लड़ाई इन्हीं अंकों को प्राप्त करने की है न कि सभी 200 अंकों को पाने की। इस प्रकार इन 110 अंकों में भारतीय राजव्यवस्था एक-तिहाई से भी अधिक का योगदान देता है। अत: अगर इस खंड को ठीक से तैयार कर लिया जाए तो प्रिलिम्स की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा।

हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि भारतीय राजव्यवस्था एक ऐसा खंड है जिससे संबंधित शत-प्रतिशत प्रश्नों को परीक्षा में सटीकता से हल किया जा सकता है। बस आवश्यकता है इस विषय की प्रकृति को ठीक से समझने की। हम यहाँ ऐसे कुछ सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं जो आपकी तैयारी को सही दिशा देने में सहायक होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि राजव्यवस्था में जितना महत्त्व तथ्य यानी संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों का है उतना ही महत्त्व उन तथ्यों की व्याख्या का भी है। जब तक 'तथ्य-व्याख्या' के अंतर्संबंध को आत्मसात नहीं कर लिया जाता तब तक प्रश्नों को सटीकता से हल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिये अनुच्छेद 20(2) को देखें–किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा– तो इस तथ्य को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि इसमें प्रयुक्त वाक्यांश 'अभियोजित और दंडित' की व्याख्या को भी समझना पड़ेगा। दूसरे बिंदु के रूप में यह कि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बीच 'समानता व असमानता' के तत्त्वों की ठीक पहचान आवश्यक है। इस संदर्भ में उदाहरण देखें तो अक्सर राज्य के नीति निदेशक तत्त्व व मौलिक कर्त्तव्यों में शामिल 'साझे प्रावधानों' से संबंधित प्रश्न पूछ लिये जाते हैं तो कभी किसी अधिकार या संस्था के संवैधानिक, सांविधिक या कानूनी प्रस्थिति के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसे में अंतरों को पहचानने की स्पष्ट दृष्टि होनी अनिवार्य है। तीसरे बिंदु की बात करें तो 'स्थायी प्रावधान व नवीन संशोधनों' के परस्पर संबंध पर पैनी नज़र होनी आवश्यक है। जैसे, नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के प्रावधानों को जानना तो जरूरी है ही साथ ही यह भी आवश्यक है कि नागरिकता संबंधी स्थायी प्रावधानों को भी ठीक से तैयार कर लिया जाए। कई बार नवीन संशोधनों से जुड़े स्थायी प्रावधानों से ही प्रश्न पूछ लिये जाते हैं। 'विस्तार और सीमितता' की समझ को चौथे बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। वस्तुत: संविधान के एक-एक अनुच्छेद से जुड़ी इतनी व्याख्याएँ हैं कि उनको समझने में पूरा जीवन खप जाए। हमें इतनी गहराई में जाने का लोभ संवरण करना होगा और परीक्षोपयोगी सामग्री तक स्वयं को सीमित करना होगा। अगर ऐसी कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित ही भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों को ठीक किया जा सकता है।

जब हमने 'Quick Book' सीरीज़ शुरू की थी तभी से आप पाठकों के इस आशय के ढेरों संदेश हमें प्राप्त हुए कि पुस्तक पढ़ने से पूरा पाठ्यक्रम तो तैयार हो जाता है किंतु प्रश्नों को हल करने में पूर्ण सहजता नहीं आ पा रही है। आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम इस समस्या को दूर करने के लिये आपको संपूर्ण अभ्यास सेट उपलब्ध कराएँ। हम आपकी इस अपेक्षा से सहमति जताते हुए 'प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़' शुरू कर रहे हैं। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उसके व्याख्या सहित उत्तर शामिल किये जाएंगे। प्रस्तुत पुस्तक राजव्यवस्था खंड से संबंधित है। इसमें 1600+ बहुविकल्पीय प्रश्नों को व्याख्या सहित शामिल किया गया है। इस पुस्तक को पूर्व में पूछे जा चुके प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाओं को समझते हुए तैयार किया गया है। वैसे तो यह पुस्तक अपने आप में संपूर्ण है किंतु यदि आप इसे 'Quick Book' सीरीज़ की 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' पुस्तक के साथ तैयार करते हैं तो फिर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपकी परिधि के बाहर नहीं होगा। आपकी सुविधा के लिये हमने दोनों ही पुस्तकों को एक-समान अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी सफलता की राह आसान बनाएगी। इन प्रश्नों के अभ्यास से आप अपनी कमज़ोरियों से परिचित हो सकेंगे और समय रहते इसे ठीक भी कर सकेंगे।

अंत में यही कि आप पुस्तक पढ़ें और इससे संबंधित अपने अनुभव हमसे साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिये सबसे महत्त्वपूर्ण है। आप अपनी बात "8130392355" नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. राजव्यवस्था : एक परिचय 1-15

2. भारतीय संविधान की विकास यात्रा 16-24

3. भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ 25-41

4. संविधान की प्रस्तावना 42-46

5. भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन 47-54

6. नागरिकता 55-61

7. मूल अधिकार 62-102

8. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 103-115

9. मूल कर्त्तव्य 116-120

10. कार्यपालिका 121-173

11. न्यायपालिका 174-204

12. विधायिका 205-271

13. केंद्र-राज्य संबंध 272-280

14. संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था 281-283

15. कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध 284-286

16. भाषा संबंधी उपबंध 287-289

17. आपात उपबंध 290-296

18. अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 297-301

19. स्थानीय स्वशासन 302-316

20. आयोग/परिषद/अधिकरण 317-351

21. भारत में निर्वाचन, मतदान व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था 352-370

22. भारत में सुशासन 371-372

23. संविधान संशोधन : एक नज़र में 373-385

24. भारतीय संविधान : सामान्य पहलू 386-393

1 राजव्यवस्था : एक परिचय (Polity : An Introduction)

1. संसदीय लोकतंत्र वह है, जहाँ-
   1. जन-सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है।
   2. सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है।
   3. सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाता है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2

उत्तर: (a)
व्याख्या: संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है। अत: कथन 1 सही है।
- अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसी कारण इसे 'उत्तरदायी सरकार' के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें सरकार विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है, जब तक उन्हें विधायिका (संसद) का विश्वास प्राप्त है। अत: कथन 2 सही है।
- संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व सांसदों को दिया जाता है अत: कथन 3 सही है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सी एक, अध्यक्षात्मक (प्रेसिडेंशियल) स्वरूप की सरकार की विशेषता है?
   (a) राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता
   (b) यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक् नहीं करता
   (c) राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है
   (d) राष्ट्रपति की पदावधि विधान-मंडल पर निर्भर करती है

उत्तर: (a)
व्याख्या: अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की निम्न विशेषताएँ होती हैं-
- राष्ट्रपति प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है।
- कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चयन या तो जनता सीधे करती है या इसी उद्देश्य के लिये निर्वाचित निर्वाचक मंडल करता है।
- राष्ट्रपति, विधानमंडल का अंग नहीं होता है। इसलिये सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकता है। अत: विकल्प (a) सही है।
- कार्यपालिका को विधायिका की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभानी होती हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन-सी एक, भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है?
   (a) प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती हैं
   (b) न्यायालयों को संविधान और सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति है
   (c) राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हैं
   (d) सरकार के हर स्तर के लिये राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं

उत्तर: (c)
व्याख्या: भारतीय परिसंघवाद की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
- यहाँ दोहरी शासन-पद्धति है- केंद्र सरकार व राज्य सरकार। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।
- संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के उपयुक्त निर्वचन और उसके संरक्षण के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
- एक लिखित संविधान की उपस्थिति।
- राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया गया है।
- एकल नागरिकता।
- राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं।
- राज्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं अपितु अलग इकाई है।

अत: विकल्प (c) सही उत्तर है।

4. अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है।
   2. कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
- राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्वाचित निर्वाचकगण द्वारा होता है।
- राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राज्याध्यक्ष नहीं होता, अपितु वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह विधानमंडल का अंग नहीं होता है।
- राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वह विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे।
- कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। अत: कथन 1 व 2 दोनों सही हैं।

2 भारतीय संविधान की विकास यात्रा (The Journey of Indian Constitution)

1. संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिये-
   1. बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना
   2. नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा-निर्देश
   3. कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना
   4. न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना
   5. यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 5
   (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: संविधान का कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।

- संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गए हैं। कोई भी सरकार कुछ विषम परिस्थितियों में ही उन्हें सीमित कर सकती है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। उसमें भी अनुच्छेद 20 व 21 के मूल अधिकार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता। साझे मूल्य, स्वतंत्रता, बंधुता व धार्मिक-राजनीतिक स्वतंत्रताएँ हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हैं।
- स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है।
- संविधान में सत्ता में आने की प्रक्रिया व उनको प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है लेकिन उनकी योग्यता के संदर्भ में इतनी चुस्ती नहीं दिखाई गई है अर्थात् ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग ही आएँ व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अत: कथन 5 असत्य है।

2. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 में किये गए प्रावधानों में से कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया।
   (b) इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिये चुना जाएगा।
   (c) इस अधिनियम के द्वारा 'बंगाल के गवर्नर' को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया।
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: (d)

व्याख्या: रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तथा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों (बंबई, मद्रास व कलकत्ता) का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 'लार्ड वारेन हेस्टिंग्स' थे। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अत: विकल्प (d) सही है।

3. निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया?
   (a) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
   (b) 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम
   (c) चार्टर अधिनियम, 1813
   (d) रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773

उत्तर: (b)

व्याख्या: 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किये गए अपने कार्यों के लिये सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। अत: विकल्प (b) सही है।

4. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया-
   (a) 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा
   (b) 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा
   (c) 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा
   (d) 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा

उत्तर: (c)

व्याख्या: चार्टर अधिनियम, 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णत: समाप्त कर दिये गए। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। अत: विकल्प (c) सही है।

3 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ
(The Making of the Indian Constitution and Its Salient Features)

1. भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
   (a) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन (b) 2 वर्ष 8 माह 12 दिन
   (c) 1 वर्ष 2 माह 12 दिन (d) 3 वर्ष 1 माह 4 दिन

उत्तर: (a)
व्याख्या: भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं, जिनमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अत: विकल्प (a) सही है।

2. भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है-
   (a) 26 नवंबर (b) 26 जनवरी
   (c) 26 दिसंबर (d) 15 अगस्त

उत्तर: (a)
व्याख्या: 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया था। अत: विकल्प (a) सही है।

3. भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को-
   (a) ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया।
   (b) गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया।
   (c) विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया।
   (d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया।

उत्तर: (c)
व्याख्या: संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया, जहाँ प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था।
उल्लेखनीय है कि बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। अत: विकल्प (c) सही है।

4. भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको/किनको तुरंत लागू किया गया?
   (a) भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध
   (b) निर्वाचन संबंधी उपबंध
   (c) अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध
   (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)
व्याख्या: 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वत: ही लागू हो गए। अत: विकल्प (d) सही है।

5. निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को 'हिंदुओं का निकाय' कहा है?
   (a) लॉर्ड विसकाउंट (b) विंस्टन चर्चिल
   (c) ऑस्टिन (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)
व्याख्या: लार्ड विसकाउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को 'हिंदुओं का निकाय' कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि, संविधान सभा ने 'भारत के केवल एक बड़े समुदाय' का प्रतिनिधित्व किया।
ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि- "संविधान सभा एक-दलीय देश का एक-दलीय निकाय है। सभी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही भारत है।" अत: विकल्प (a) सही है।

6. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और नीचे दिये गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिये-

सूची-I (भारत के संविधान के लक्षण)	सूची-II (किस देश से गृहीत)
A. मूल अधिकार	1. यू.के.
B. संसदीय शासन प्रणाली	2. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. आपात उपबंध	3. आयरलैंड
D. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व	4. जर्मनी
	5. कनाडा

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	5	1
(b)	5	1	3	4
(c)	2	1	4	3
(d)	1	2	4	3

4 संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है।
   2. उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है।
   3. उद्देशिका 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'संकल्पित उद्देश्यों' पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा तैयार किया गया तथा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में तीन नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। एलआईसी मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्त्वपूर्ण भाग माना गया है। अत: कथन 3 सही है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का भाग भी माना तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना है। अत: कथन 1 सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं-
  - प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इसके प्रावधान न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है।

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा क्रम सही है?
   (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी
   (b) पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी
   (c) लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष
   (d) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (d)

व्याख्या: संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में रखे गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' से हुआ है, इसलिये इसे 'उद्देशिका' कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे क्रम में हुई है। अत: विकल्प (d) सही है।

नोट – 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द शामिल किये गए हैं।

3. 'प्रस्तावना' में संविधान का क्या निहित है?
   (a) मूल दर्शन (b) प्रत्यक्ष लोकतंत्र
   (c) साम्यवादी स्वरूप (d) नास्तिक राज्य

उत्तर: (a)

व्याख्या: प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की भाँति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। अत: विकल्प (a) सही है।

4. 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न' शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?
   (a) केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति
   (b) केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति
   (c) आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति
   (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न' से आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी देश का डोमिनियन है अर्थात् भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। अत: विकल्प (c) सही है।

5. भारत में लोकतंत्र का कौन-सा स्वरूप प्रचलित है?
   (a) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (b) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
   (c) दोनों का मिश्रित स्वरूप (d) दोनों में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: लोकतंत्र दो प्रकार का होता है–प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे– स्विट्ज़रलैंड का लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहाँ लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। अत: विकल्प (b) सही है।

5 भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन
(Union of India and its Territory and Reorganisation of States)

1. भारत के राज्यक्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं।
   2. प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं।
   3. इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किये जा सकते हैं।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: संविधान के भाग-I में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है।

- संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। जिसमें 'भारत' शब्द देश का नाम व 'संघ' शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है।
- राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- भारत के राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे-
  - राज्यों के राज्यक्षेत्र। अत: कथन 1 सही है।
  - पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र। अत: कथन 2 सही है।
  - ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ। अत: कथन 3 सही है।

2. राज्य का नाम बदलने के लिये संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
   2. इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है।
   3. इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों की सीमाओं या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमाएँ बदलने के लिये कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिये सिफारिश करें। अत: कथन 1 सही है।

- विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार/राय व्यक्त करते हुए विधेयक वापस भेजना होगा। संसद इन विचारों को मानने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भू-भाग या नाम आदि को बदल सकती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- अनुच्छेद 4 के अनुसार, नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2) नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3) संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

3. भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं, जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिये अनुच्छेद-368 के अधीन संशोधन के बिना, उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिये सशक्त करते हैं। उनमें शामिल हैं-
   1. अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित)
   2. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि (नए राज्यों के निर्माण से संबंधित)
   3. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2); नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3) संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जायेगा। अत: कथन 1 व 2 सही है।

- अनुच्छेद 4(2) के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिये बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद-368 के प्रयोजनों के लिये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अत: कथन 3 सही है।

4. भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति/पद्धतियाँ सही है/हैं?
   1. साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा।

6 नागरिकता (Citizenship)

1. भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है?
   (a) भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक
   (b) भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक
   (c) भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक
   (d) भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक

उत्तर: (b)
व्याख्या: संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में संपूर्ण देश के लिये एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है।
ध्यातव्य है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों, जैसे-कंपनी, निगम आदि को नहीं। अत: विकल्प (b) सही है।

2. नागरिकता का अर्थ है-
   1. नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार
   2. लोक सभा (संघ की) और हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिये मताधिकार
   3. संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा होती हैं। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं तथा 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अत: कथन 2 सही है।
- नागरिकों को संसद एवं राज्य विधानमण्डल की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। अत: कथन 3 सही है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारत में इकहरी (एकल) नागरिकता का प्रावधान है।
   2. संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
   3. एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: सभी विकल्प सही हैं। ध्यातव्य है कि संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 को लागू किया और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गए, जो मुख्यत: निम्न हैं- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986; 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं हैं।
   2. संविधान का भाग-2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है, जो 26 जनवरी, 1950 से भारत के नागरिक बने।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। साथ ही, संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इस संबंध में संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं हैं। अत: विकल्प (c) सही है।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
   (a) नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग-3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है।
   (b) भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू-क्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है।
   (c) संविधान में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है।
   (d) सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका (ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम) पर 1985 में एक महत्त्वपूर्ण फैसला दिया।

उत्तर: (a)
व्याख्या: नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में नहीं बल्कि दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। अत: कथन (a) असत्य है। शेष तीनों कथन सत्य हैं।

7

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

1. निम्नलिखित में से किनको 'अधिकार' के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा?
   1. अधिकार, व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है।
   2. अधिकार, व्यक्ति का कर्त्तव्य बोध है।
   3. अधिकार, व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंधन है।
   4. अधिकार, लोगों के तार्किक दावे हैं, जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है।

   कूट:
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) 1 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: वस्तुत: अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें, जो हम सबके लिये हितकर हैं।
   2. अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें।
   3. टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिये।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: अधिकार हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखकर आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया दी जा सकती है जिससे कि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। ओज़ोन परत की हिफाज़त करना, वायु और जल प्रदूषण कम-से-कम करना, वृक्षों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना आदि। अत: कथन 1 सही है।

- अगर मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिये तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंद में दखलंदाज़ी से बचना होगा। अत: कथन 2 सही है।
- टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूँ और उसे इंटरनेट पर डाल दूँ, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अत: टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

3. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

कथन	संबंधित व्यक्ति
1. निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए।	जॉन रॉल्स
2. न्यायपूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।	जे. एस. मिल
3. 'न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है, जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत; बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।	डॉ. भीम राव अंबेडकर

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: युग्म 1 सुमेलित है, सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत यह कथन न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर दिया गया है।

कथन 2 संविधानविद् डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है अत: यह युग्म 2 सुमेलित नहीं है।

कथन 3 प्रसिद्ध आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक चिंतक जे. एस. मिल द्वारा लिखा गया है अत: युग्म 3 भी सुमेलित नहीं है।

8 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy-DPSP)

1. भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा देश के शासन के लिये आधारभूत है?
   (a) मूल अधिकार (b) मूल कर्त्तव्य
   (c) नीति निदेशक तत्त्व (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)
व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक) को देश के शासन में आधारभूत तत्त्वों के रूप में शामिल किया गया है।
- अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के भाग 4 में नीति के निदेशक तत्त्वों को शामिल किया गया है।

2. भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?
   (a) उद्देशिका (b) नीति निदेशक तत्त्व
   (c) मूल अधिकार (d) सातवीं अनुसूची

उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में किया गया है।
- 'कल्याणकारी राज्य' से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय हो। नीति के निदेशक तत्त्वों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय स्थापित करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किये गए हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं।
- अनुच्छेद 38(1) में स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 38(2) में स्पष्ट किया गया है कि राज्य विशेषत: आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 39 में लैंगिक समानता को स्थापित करने की बात कही गई है।
- अनुच्छेद 39(क) में पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार अनुच्छेद 39(घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय संविधान में नीति के निदेशक तत्त्वों को आयरलैण्ड के संविधान से ग्रहण किया गया है।

3. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
   2. इन तत्त्वों में अन्तर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 37 के अनुसार, इस भाग (अर्थात् भाग 4; अनुच्छेद 36 से 51 तक) के अंतर्गत शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

4. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है?
   (a) संविधान की उद्देशिका में
   (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में
   (c) मूल कर्तव्यों में
   (d) नौवीं अनुसूची में

उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत के संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के खण्ड में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है।
अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य-
- अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
- राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
- संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और
- अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

5. भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का किसमें उपबंध किया गया है?
   (a) उद्देशिका और मूल अधिकार
   (b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
   (c) मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
   (d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

9

मूल कर्त्तव्य
(Fundamental Duties)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित नहीं है/हैं?
   1. हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना।
   2. अपनी सामासिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना।
   3. समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
   4. ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्त्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: 'सरदार स्वर्ण सिंह' समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग 4क के अंतर्गत अनुच्छेद 51क में 10 मूल कर्त्तव्य जोड़े गए। इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ मौलिक कर्त्तव्य संविधान में शामिल किया गया।

मूल कर्त्तव्य-

1. संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुये प्रयत्न और उपलब्धि की नई उँचाइयों को छू ले।
11. माता-पिता या संरक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

अत: कथन 3 एवं 4 का संबंध मूल कर्त्तव्य से नहीं है।

2. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है/हैं?
   1. मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा
   2. सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा
   3. वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास
   4. वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयत्न

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
   (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: मिश्रित (सामासिक) संस्कृति की गौरवशाली एवं समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास तथा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयत्न आदि सभी मूल कर्त्तव्यों में शामिल हैं जबकि सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्त्तव्यों में शामिल नहीं है।

3. भारत में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. इनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था।
   2. इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है।
   3. मौलिक कर्त्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: 6 से 14 वर्ष के बच्चों या प्रतिपालित को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- मूल कर्त्तव्यों में नैतिक कर्त्तव्य के साथ-साथ नागरिक कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है जैसे- स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना नैतिक कर्त्तव्य है जबकि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नागरिक कर्त्तव्य है। अत: कथन 2 सही है।
- मूल कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत नहीं कराए जा सकते हैं लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करवाने की शक्ति रखती है। अत: कथन 3 सही है।

21. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्य के रूप में उल्लिखित **नहीं** किया गया है?

(a) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना।

(b) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

(c) वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना।

(d) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

उत्तर: (d)

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्त्व बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना अनुच्छेद 51 के तहत नीति-निदेशक तत्त्वों का हिस्सा है। अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

Think IAS दृष्टि The Vision Think Drishti

आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है

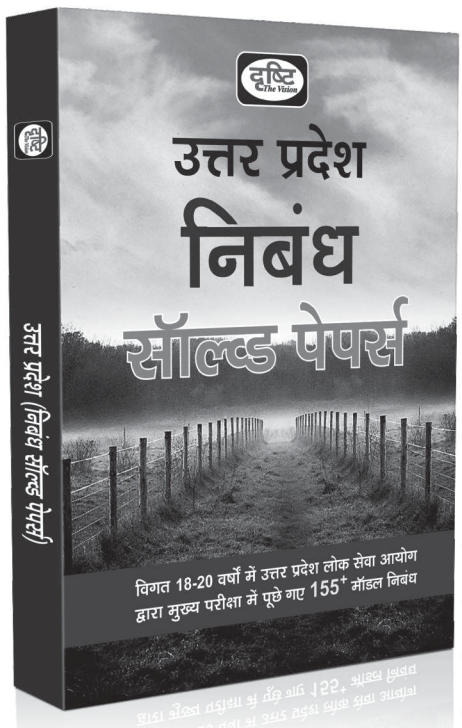

उत्तर प्रदेश निबंध सॉल्व्ड पेपर्स

प्रमुख आकर्षण

- विगत 20 वर्षों में UPPCS की मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंधों का वर्षवार एवं खंडवार हल
- 155+ मॉडल निबंधों का संकलन
- निबंधों में उद्धरणों, कथनों, काव्यांशों आदि का समुचित उपयोग
- सहज, बोधगम्य एवं सुरुचिपूर्ण भाषा-शैली
- आगामी मुख्य परीक्षा के लिये अत्यंत उपयोगी

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

10 कार्यपालिका (The Executive)

खंड-क : संघ की कार्यपालिका

1. निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का/के अंग है/हैं?
   1. भारत का राष्ट्रपति
   2. भारत का प्रधानमंत्री
   3. भारत का महान्यायवादी

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान हैं।
भारतीय संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं:
1. राष्ट्रपति 2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री 4. मंत्रिपरिषद
5. भारत का महान्यायवादी

अत: **(d)** सही उत्तर होगा।

2. संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्त्तव्यों का पालन करना है?
   1. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना।
   2. यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हों।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को दो कर्तव्यों का पालन करना है:
- यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें।
- सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित हो रही है।

अत: विकल्प (c) सही है।

3. राष्ट्रपति पाँच वर्ष तक अपने पद पर रहता है-
   (a) अपने निर्वाचन की तारीख से
   (b) संसद द्वारा निर्धारित तिथि से
   (c) अपने पद ग्रहण के दिन से
   (d) निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से

उत्तर: (c)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अत: विकल्प (c) सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
   (a) लोकसभा (b) राज्यसभा
   (c) राज्यों की विधानपरिषदें (d) राज्यों की विधानसभाएँ

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, वहीं अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं (अर्थात् लोकसभा एवं राज्यसभा)। अत: विकल्प (d) सही है।

5. निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है?
   (a) राज्यपाल को (b) मुख्यमंत्री को
   (c) प्रधानमंत्री को (d) राष्ट्रपति को

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अत: विकल्प (d) सही है।

6. संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु-
   (a) चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा
   (b) अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगा
   (c) निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी
   (d) एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं।

11

न्यायपालिका
(The Judiciary)

1. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने घोषणा की कि मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होता है। यहाँ 'मास्टर ऑफ रोस्टर' का क्या अर्थ है?
   (a) यह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने संबंधी अनिवार्य प्रावधान को संदर्भित करता है।
   (b) यह मामलों की सुनवाई के लिये बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है।
   (c) यह संसद द्वारा अपनी संवैधानिक वैधता के संदर्भ में बनाए गए किसी भी कानून की वैधता तय करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को संदर्भित करता है।
   (d) यह मूल, अपीलीय तथा परामर्शी क्षेत्राधिकार के बीच अंतर करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को संदर्भित करता है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: मुख्य न्यायाधीश 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होता है, जिसका अर्थ है कि केवल वह न्यायालय की पीठों का गठन करने और इस तरह गठित की गई पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार रखता है।' कोई भी न्यायाधीश स्वयं किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे यह आवंटित नहीं किया गया हो। अत: विकल्प (b) सही है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने की स्थिति में, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है।
   2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालाँकि वे अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना आवश्यक समझे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालाँकि, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो, को तदर्थ आधार पर नियुक्ति का अनुरोध कर सकता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 (4) का संबंध किससे है?
   (a) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये।
   (b) मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को मान्यता प्रदान करने के लिये।
   (c) उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये।
   (d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अत: विकल्प (a) सही है।

4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।
   2. न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के कार्य का नियमन करता है।
   3. महाभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना चाहिये।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 2
   (d) 1, 2 और 3

12 विधायिका (Legislature)

खंड-क : संसद

1. लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है।
   2. इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है।
   3. वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 3
   (c) केवल 3 (d) 1, 2, एवं 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। किंतु वर्तमान में यह संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य, राज्यक्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल-भारतीय समुदाय से हैं। अत: विकल्प (d) सही है।
नोट: 25 जनवरी, 2020 से लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालाँकि वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे।

2. लोकसभा के कम-से-कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं?
   (a) वर्ष में एक बार (b) वर्ष में दो बार
   (c) वर्ष में तीन बार (d) वर्ष में चार बार

उत्तर: (b)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा अर्थात् एक वर्ष में कम-से-कम दो सत्र बुलाए जाते हैं। अत: विकल्प (b) सही है।

3. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है।
   2. इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है।
   3. वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 3
   (c) केवल 3 (d) 1, 2, एवं 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है किंतु वर्तमान में यह 245 है। अत: विकल्प (d) सही है।

4. राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं-
   (a) राज्यों की विधानसभाओं द्वारा
   (b) राज्यों की विधानपरिषदों द्वारा
   (c) नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा
   (d) राज्यों की विधानसभा व विधानपरिषदों द्वारा

उत्तर: (a)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। अत: विकल्प (a) सही है।

5. राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
   (a) इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं।
   (b) इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं।
   (c) इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं।
   (d) इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं।

उत्तर: (a)
व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अत: विकल्प (a) सही है।

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही-सही वर्णित करता है?
   (a) इनमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है।
   (b) इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएँ हैं।
   (c) इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है।
   (d) इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है।

उत्तर: (d)
व्याख्या: भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2) के तहत राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान किये गए हैं। अत: विकल्प (d) सही है।

13 केंद्र-राज्य संबंध (Center-State Relations)

1. संसद की विधायी शक्ति में विधियाँ बनाना सम्मिलित है-
   1. संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रगणित किसी भी विषय पर।
   2. राज्य सूची की प्रविष्टियों के संबंध में, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इसे वांछनीय मानें।
   3. किसी देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिये, चाहे वह राज्य सूची में आता है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है। इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि "संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।" अत: कथन 1 सही है।
- अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं तो संसद, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। अत: कथन 2 सही है।
- अनुच्छेद 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई कि वह भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि के विनिश्चय को लागू करने के लिये विधि पारित कर सकती है तथा ऐसी विधि संपूर्ण राज्यक्षेत्र या किसी भाग के लिये हो सकती है। अत: कथन 3 सही है।

2. भारत के संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. अवशिष्ट शक्तियाँ संघ की संसद को दी गई हैं।
   2. अवशिष्ट शक्ति के मामले में, भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है।
   3. भारत के संविधान की अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों की सूची दी गई है।
   4. भारत शासन अधिनियम, 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गईं।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 4 (d) केवल 4

उत्तर: (c)
व्याख्या: संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों (अनुच्छेद 246) में विधि निर्माण के विषयों को वर्गीकृत किया गया है-
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
- वे विषय जो 7वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, वे अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
- भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
- भारत शासन अधिनियम, 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थीं। अत: विकल्प (c) सही है।

3. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बँटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिये आवश्यक है-
   (a) संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी
   (b) संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी
   (c) संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत
   (d) संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी

उत्तर: (d)
व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. भारत के संविधान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्पष्ट कार्य-क्षेत्र हैं।
   2. कार्य-क्षेत्र संबंधी विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय किये जाने का प्रावधान है।
   3. संविधान में आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ केंद्र सरकार की ओर झुकी हुई हैं।
   4. भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में मौन है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
   (a) 1 और 3
   (b) 2 और 4
   (c) 1, 2 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी

14 संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था (Governance System of Union Territories)

1. संघ राज्यक्षेत्रों के गठन के आधार हो सकते हैं:
   1. राजनीतिक व प्रशासनिक। 2. सामरिक महत्त्व।
   3. सांस्कृतिक भिन्नताएँ।
   4. पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लिये विशेष बर्ताव व देखभाल।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) के गठन के निम्नलिखित आधार हैं-
1. राजनीतिक व प्रशासनिक आधार पर
2. सांस्कृतिक भिन्नता
3. सामरिक महत्त्व
4. पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिये विशेष बर्ताव व देखभाल

2. संघ राज्यक्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   1. दिल्ली और पुदुच्चेरी दोनों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं।
   2. दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के पास अपना विधानमंडल नहीं है।
   3. इनके कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है तथा राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है; यह लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति एक राज्य के गवर्नर को आस-पास के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी (1963 में) और दिल्ली (1992 में) के लिये विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक परिषद का प्रावधान किया गया है। शेष संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे प्रमुख राजनीतिक संस्थान नहीं हैं। लेकिन, संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे संस्थानों की स्थापना राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण को कम नहीं करती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- पृथक उच्च न्यायालय वाला एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

3. संघ राज्यक्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण किया जाता है-
   (a) संसद द्वारा (b) उच्चतम न्यायालय द्वारा
   (c) राष्ट्रपति द्वारा (d) राज्यपाल द्वारा

उत्तर: (c)
व्याख्या: संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। अत: विकल्प (c) सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेशों हेतु विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन कर सकती/सकता है?
   (a) राष्ट्रपति (b) संसद
   (c) उच्चतम न्यायालय (d) उच्च न्यायालय

उत्तर: (b)
व्याख्या: उपर्युक्त संदर्भ में शक्ति संसद को प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, पुदुच्चेरी व जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों हेतु विधानमंडल सृजित किये हैं।

5. केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है/हैं?
   1. संविधान के भाग-VIII में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनिक संरचना का उल्लेख किया गया है।
   2. संघ राज्यक्षेत्र पुदुच्चेरी केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है।

   नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)
व्याख्या: संविधान के भाग-VIII के अन्तर्गत अनुच्छेद 239-241 में संघ राज्यक्षेत्रों की प्रशासनिक संरचना का उल्लेख किया गया है। पुदुच्चेरी, मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। अत: विकल्प (a) सही उत्तर होगा।

6. अनुच्छेद 239 संबंधित है-
   (a) दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से
   (b) संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से
   (c) संघ राज्यक्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय से
   (d) इनमें से कोई नहीं

15 कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध (Special Provisions for Some States)

1. कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. ये प्रावधान संविधान में मूलत: उपस्थित थे।
   2. राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों का उद्देश्य राज्यों के आदिवासियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के संविधान के भाग XXI (अनुच्छेद 371 से 371 J) में बारह राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, असम और मणिपुर के लिये विशेष प्रावधान हैं।

- मूलत: भारतीय संविधान में इन राज्यों के लिये किसी प्रकार का विशेष प्रावधान उल्लिखित नहीं था। इन्हें विभिन्न अनुवर्ती संशोधनों द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इन राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों का उद्देश्य है:
  - राज्य के पिछड़े क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना।
  - राज्य के आदिवासियों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना। अत: कथन 2 सही है।
  - राज्य के कुछ भागों में व्याप्त विधि-व्यवस्था की अराजक स्थिति से निपटना।
  - राज्य के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना।

2. संविधान के भाग-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. इसमें कुछ राज्यों के लिये उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है।
   2. यह भाग पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवासी स्थानों के लिये है।
   3. इस भाग द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अपनी संस्कृति एवं इतिहास को बनाए रख सकती हैं।
   4. इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सत्य हैं?
   (a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 3 और 4
   (c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर : (d)

व्याख्या : संविधान के भाग-21 में उपर्युक्त सभी कथन सम्मिलित हैं।

3. कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. संविधान के भाग-XXI में अनुच्छेद 371 से 371ञ तक बारह राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान हैं।
   2. अनुच्छेद 371क नगालैंड के विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
   3. 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने असम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: संविधान के भाग-XXI में अनुच्छेद 371 से 371ञ तक बारह राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिये विशेष प्रावधान हैं। अत: कथन 1 सत्य है।

- अनुच्छेद 371क नगालैंड के लिये विशेष प्रावधान करता है। अत: कथन 2 सत्य है।
- 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 में सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। इसमें नया अनुच्छेद 371च शामिल था जिसमें सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान थे। अत: कथन 3 सत्य नहीं है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. संविधान के अनुच्छेद 371क के तहत भूमि के स्वामित्व के संबंध में संसद के अधिनियम स्वत: नगालैंड पर लागू नहीं होते हैं।
   2. अनुच्छेद 371घ में केवल आंध्र प्रदेश के लिये प्रावधान है।
   3. अनुच्छेद 371घ के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण से अपील राज्य उच्च न्यायालय में की जाएगी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही **नहीं** हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

16 भाषा संबंधी उपबंध (Language Related Provisions)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, हिन्दी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी।
   2. राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत उच्च न्यायालयों के काम-काज की भाषा हिन्दी या अंग्रेज़ी हो सकती है।
   3. केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
   4. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना (हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु) 1986–87 में शुरू की गई थी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
   (c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: अनुच्छेद 343(1) उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। अत: कथन 1 सही है।
- उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेज़ी भाषा में होगी (जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न कर दे)। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- हिन्दी के उन्नयन हेतु केंद्रीय हिन्दी समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसी क्रम में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना की शुरुआत 1986–87 में की गई थी। अत: कथन 3 व 4 सही है।

2. भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने के उद्देश्य हैं:
   1. इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
   2. इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का उपयोग हिन्दी भाषा की समृद्धता के लिये भी किया जा सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में आठवीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं के विशिष्ट विवरण के पीछे दो उद्देश्य हैं:
- इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। अत: कथन 1 सही है।
- इन भाषाओं के रूपों, शैली और अभिव्यक्ति का उपयोग हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिये किया जाना है। अत: कथन 2 सही है।

3. संविधान में उल्लिखित भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
   (a) संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में संघ या राज्य के किसी सरकारी कार्यालय में शिकायत करने का अधिकार।
   (b) प्रत्येक राज्य द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षित करने के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना।
   (c) राष्ट्रपति भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक रक्षोपायों से सम्बद्ध सभी मामलों की जाँच के लिये एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो उसे रिपोर्ट करेगा।
   (d) संविधान केंद्र पर हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन प्रसार और विकास के लिये कोई कर्तव्य आरोपित नहीं करता है।

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान अनुच्छेद 351 के ज़रिये केंद्र पर हिन्दी भाषा के प्रसार और विकास के लिये कर्तव्य आरोपित करता है। अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

4. क्षेत्रीय भाषा संबंधी निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिये-
   1. किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के लिये एक या एक से अधिक भाषा का चुनाव राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कर सकती है, लेकिन जब तक यह न हो तो उस राज्य की आधिकारिक भाषा हिन्दी होगी।
   2. केंद्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में केवल संघ की राजभाषा का प्रयोग होगा।
   3. जब राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता मिले, तो वह ऐसी भाषा को मान्यता दे सकता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही नहीं है/हैं?

   (a) केवल 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान में राज्यों के लिये किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में कुछ उपबंध किये गए हैं। किसी राज्य की विधायिका एक या एक से अधिक भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में चुन सकती है लेकिन जब तक यह न हो तब तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी होगी। अत: कथन 1 गलत है।

17 आपात उपबंध (Emergency Provisions)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह–
   (a) बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करें।
   (b) किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विचार अनुज्ञात करें।
   (c) यह घोषणा करें कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे।
   (d) संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भाग-18 के अंतर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 355 का संबंध संघ के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा और दायित्व से है। अत: विकल्प (a) सही है।

2. भारत के संविधान के भाग-18 में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, हालाँकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता।
   2. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिये विशेष बहुमत आवश्यक है, जबकि वित्तीय आपातकाल को केवल साधारण बहुमत द्वारा ही लागू किया जा सकता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है परंतु राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं। अत: कथन 1 सही है।

- राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा व जारी करने का प्रस्ताव संसद द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है, जबकि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक बनाया गया है। अत: कथन 2 सही है।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य:** एक बार संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के पश्चात् वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिये जारी रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस नहीं ली जाती। जबकि राष्ट्रीय आपात संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद छह महीने तक जारी रह सकता है तथा प्रत्येक छह माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है व उद्घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति की अनुवर्ती घोषणा से या लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर की जा सकती है।

3. भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) संघ कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं।
   (b) संघ कार्यपालिका, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है।
   (c) भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियों जैसी कोई शक्ति राज्यपालों को प्राप्त नहीं है।
   (d) यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो वे राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।

उत्तर: (d)

व्याख्या: संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352-360 तक आपातकालीन उपबंध दिये गए है।

- अनुच्छेद 353क में बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। अत: कथन (a) सही है।
- भारत में राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) व वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360) की उद्घोषणा की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। अत: कथन (c) सही है।
- अनुच्छेद 360 (1) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अत: कथन (d) सही नहीं है।

18 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र (The Scheduled and Tribal Areas)

1. संविधान में उल्लिखित 'पाँचवी तथा छठी अनुसूची' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार का होता है।
   2. इनके तहत जनजातीय सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है।
   3. इनके तहत राज्यपाल स्वायत्त ज़िलों और स्वायत्त क्षेत्रों को अधिसूचित करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही **नहीं** है/हैं?
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या:
- पाँचवी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक संघ का कार्यकारी अधिकार होता है किंतु छठी अनुसूची के मामले में राज्य का कार्यकारी अधिकार होता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- पाँचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन किया जाता है जबकि छठी अनुसूची के तहत राज्यपाल ज़िलापरिषद् तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिषद् का गठन करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- छठी अनुसूची के तहत राज्यपाल को अधिसूचना द्वारा स्वायत्त ज़िले एवं स्वायत्त क्षेत्र बनाने का अधिकार है। अत: कथन 3 सहीं नहीं है।

2. 'अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. संविधान की पाँचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है।
   2. राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।
   3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनूसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)
व्याख्या: अनुच्छेद 244(1) के तहत संविधान की पाँचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा)। अत: कथन 1 सही है।
- असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र की राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- राज्यपाल अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना, केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध अनुसूची 6 में है।
   2. ये जनजातीय क्षेत्र 'स्वशासी' ज़िले के रूप में प्रशासित किये जाते हैं, जिनकी कार्य पद्धति हेतु ज़िला परिषद और प्रादेशिक परिषदों का सृजन किया गया है।
   3. इन परिषदों को न्यायिक, सिविल और दांडिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
   4. इन परिषदों को भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण की तथा कुछ निर्दिष्ट कर लगाने की भी शक्ति प्राप्त है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1, 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधानों का वर्णन है। अत: कथन 1 सही है।
- इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिये स्वायत्तशासी ज़िलों का गठन किया गया है। प्रत्येक स्वायत्तशासी ज़िले के लिये एक ज़िला परिषद तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी क्षेत्र में अलग प्रादेशिक परिषद हैं। इन परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- वे भूमि, वन, नहर, सामाजिक रुढ़ियों आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं लेकिन सभी विधियों हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। ये परिषदें ग्राम न्यायालयों का गठन भी कर सकती हैं। इस प्रकार परिषदों को न्यायिक, सिविल और दाण्डिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अत: कथन 2 व 3 सही है।
- ज़िला एवं प्रादेशिक परिषदों को भू-राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वे कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकती हैं। अत: कथन 4 सही है।

19 स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)

1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है
   (a) संघवाद का
   (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
   (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
   (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

व्याख्या: लोकतंत्र में शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके दो मूल तत्त्व हैं–(1) यह राज्य की शासन व्यवस्था को निचले स्तर तक विकेंद्रीकृत करता है। (2) यह लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को संभव बनाता है। भारत में 24 अप्रैल, 1993 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। अत: विकल्प (b) सही है।

2. जब संविधान बना तो स्थानीय शासन को अनिवार्य प्रावधान न बनाकर इसे 'राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत' के अंतर्गत शामिल करने के कारण थे-
   1. देश-विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मज़बूत बनाने का रहा।
   2. नेहरू खुद अति-स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये खतरा मानते थे।
   3. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते थे।
   4. महात्मा गांधी स्थानीय शासन के समर्थक नहीं थे।

   कूट:
   (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही कारण हैं।

महात्मा गांधी गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय शासन को अनिवार्य बनाने के पक्षधर थे। अत: कथन 4 सही नहीं है।

3. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
   1. विकास में जन-भागीदारी
   2. राजनीतिक जवाबदेही
   3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
   4. वित्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: विकास की प्रक्रिया में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है।

- सरकार की प्रणाली को स्थानीय स्तर तक पहुँचाने के लिये ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।
- 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर लागू किया गया जिससे भारत में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर (त्रिस्तरीय) लोकतांत्रिक प्रणाली को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सका।
- पंचायती राज व्यवस्था के तहत मतदाताओं के द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार में भागीदारी करने लगें।

4. स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
   2. गाँव व ज़िला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं।
   3. स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं।
   4. जीवंत और मज़बूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सत्य हैं?
   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अत: 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एवं 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

20 आयोग/परिषद/अधिकरण (Commissions/Councils/Tribunals)

1. निम्नलिखित में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य कौन-से हैं?
   1. सिविल सेवा और सिविल पदों के लिये केंद्र सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसी। इसके कार्यों में समूह 'ए' के राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति के आधार पर विभागीय नियुक्तियाँ करना भी सम्मिलित है।
   2. नियुक्ति, पदोन्नति, अंतर्सेवा स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थानांतरणों के लिये अभ्यर्थी की अनुकूलता के मामलों से संबंधित सिद्धांतों पर सरकार के लिये सलाहकारी निकाय।
   3. सिविल सेवा और सिविल पदों के लिये नियुक्ति करने वाला निकाय।
   4. प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देने के लिये प्राथमिक निकाय।
   5. भारत सरकार में सेवारत या पूर्व-सेवारत किसी व्यक्ति का कोई दावा या उसके विरुद्ध योजित वाद के प्रतिवाद में लगे व्यय के अभ्यर्थन की प्रतिपूर्ति करना।

   कूट-
   (a) 1, 2, 3 और 4
   (b) 1, 2, 3, 4 और 5
   (c) 1, 3, 4 और 5
   (d) 1, 2, 4 और 5

उत्तर: (d)
व्याख्या: नियुक्ति करने वाला निकाय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) है। अत: 3 सही नहीं है, शेष सभी सही हैं।

2. 'संघ लोक सेवा आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. यह सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण को विनियमित करता है।
   2. संघ लोक सेवा आयोग सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करता है।
   3. राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)
व्याख्या:
- सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, काडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संघ लोक सेवा आयोग का कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग देखता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर तथा सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति व जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्कता नहीं है। परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिये संसद के सदन में रखना होगा। अत: कथन 3 सही है।

3. 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) के अध्यक्ष के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. अनुच्छेद 314 के तहत संघ एवं राज्यों के लिये लोक सेवा आयोग का उपबंध किया गया है।
   2. संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 ओर 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)
व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में उपबंध है। अत: कथन 2 सही है।

4. 'संघ लोक सेवा आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. संविधान में इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है।
   2. इसके सदस्यों के वेतन-भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
   3. इसके सदस्यों के वेतन-भत्तों का निर्धारण संसद करती है।

21 भारत में निर्वाचन, मतदान व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था
(Elections, Voting Behaviour and Party System in India)

1. दल-बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) ये उपबंध, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में दिये गए हैं।
   (b) दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य किया जा सकता है।
   (c) दल-बदल के आधार पर अयोग्यता, विलय के मामले में लागू नहीं होती है।
   (d) दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किये जाते हैं।

उत्तर: (d)

व्याख्या: 52वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा दल बदल कानून लाया गया जिसके द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर उनकी निर्योग्यता का प्रावधान किया गया तथा इसके तहत नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। अत: विकल्प (a) व (b) सही है।

- दल का विभाजन होने अर्थात् कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा मिलकर कोई नया दल बनाने तथा विलय होने पर यह कानून लागू नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि पीठासीन अधिकारी चुना जाता है तो वह स्वैच्छिक रूप से दल से बाहर चला जाएगा और कार्यकाल समाप्ति के बाद पुन: अपने दल का सदस्य बन जाएगा तो उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में भी यह नियम लागू नहीं होगा। अत: विकल्प (c) सही है।
- दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्हरता संबंधी प्रश्न पर अंतिम निर्णय उस सदन का अध्यक्ष करता है। अत: विकल्प (d) सही नहीं है।

  1993 में किहोतो होलोहन मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है।

2. 'दलबदल के आधार पर निरर्हता' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. अगर कोई नामित सदस्य 6 माह के अंदर किसी राजनैतिक दल में शामिल होता है।
   2. अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है।
   3. अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल कानून के तहत सांसदों एवं विधायकों की निरर्हताएँ वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ दे।
2. यदि वह अपने राजनीतिक दल के विपरीत मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। अत: कथन 3 सही है।
3. अगर निर्दलीय सदस्य किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है। अत: कथन 2 सही है।
4. यदि कोई नामित सदस्य छ: माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

3. दसवीं सूची के तहत निरर्हता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है?
   (a) राष्ट्रपति (b) निर्वाचन आयोग
   (c) सदन का अध्यक्ष/सभापति (d) उच्चतम न्यायालय

उत्तर: (c)

व्याख्या: दसवीं अनुसूची (दल-बदल) के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्य सभा में सभापति व लोक सभा में अध्यक्ष करता है न कि भारत का राष्ट्रपति। किहोतो होलोहान मामले (1992) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति/अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अत: विकल्प (c) सही है।

4. दल-बदल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या निर्देशन के विपरीत मतदान करे या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो इसे दल-बदल कहते हैं।
   2. दल-बदल विवादों पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है।
   3. 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल-बदल निरोधक कानून लाया गया।
   4. दल-बदल सिद्ध होने पर उक्त सदस्य की सदन में सदस्यता समाप्त हो जाती है साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी राजनैतिक पद हेतु भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

22 भारत में सुशासन (Good Governance in India)

1. नागरिक चार्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. नागरिक चार्टर एक दस्तावेज़ है जो संगठन के नागरिकों की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
   2. नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।
   3. नागरिक चार्टर पहल केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों पर ही अपना अधिकार रखता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: नागरिक चार्टर एक दस्तावेज़ है, जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना है। नागरिक चार्टर मूलत: संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मानकों के संबंध में उसके द्वारा की गई वचनबद्धताओं का एक सेट है। अत: कथन 1 सत्य है।

- नागरिक चार्टर कानूनी तौर पर प्रवर्तित नहीं किया जाता इसलिये यह गैर-वाद योग्य है। हालाँकि यह विनिर्दिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा आदि सहित नागरिकों को सेवाओं की सुपुर्दगी में सहायता के लिये एक साधन है जो यह संगठन और उसके ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं से निर्मित होता है। अत: कथन 2 सत्य नहीं है।
- चार्टर की पहल में न केवल केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के विभाग/एजेंसियाँ भी आती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के विभिन्न विभागों/एजेसियों ने अपना चार्टर बनाया है। अत: कथन 3 सत्य नहीं है।

2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
   2. लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जाँच एजेंसी के अधीक्षण और निदेशन की शक्ति होगी।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- यह अधिनियम देश को एकसमान सतर्कता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध रोडमैप प्रदान कराने के लिये केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य तथा A, B, C और D श्रेणी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी आते हैं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में कुछ विशेष प्रक्रियाओं के साथ शामिल किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- लोकपाल में यह अधिकार निहित किया गया है कि वह स्वयं द्वारा प्रेषित मामलों पर किसी भी जाँच एजेंसी, (जिसमे CBI भी शामिल है) का अधीक्षण और दिशा-निर्देशन कर सके। अधिनियम में किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ही लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की व जब्त करने संबंधी प्रावधान भी दिये गए हैं। अत: कथन 2 सही है।

3. 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, संसद सदस्य और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
   2. लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जाँच एजेंसी के अधीक्षण और निदेशन की शक्ति होगी।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- यह अधिनियम देश को एकसमान सतर्कता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध रोडमैप प्रदान कराने के लिये केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य तथा A, B, C और D श्रेणी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी आते हैं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में कुछ विशेष प्रक्रियाओं के साथ शामिल किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

23 संविधान संशोधन : एक नज़र में (Constitutional Amendments : At a Glance)

1. भारत के संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
   (a) एक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
   (b) प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा संशोधन विधेयक पारित होना चाहिये।
   (c) किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों से अनुसमर्थन करवाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
   (d) भारत के राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं।

उत्तर: (c)

व्याख्या: संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है।

- संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अत: विकल्प (a) सही है।
- विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिये। अत: विकल्प (b) सही है।
- यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिये। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। अत: विकल्प (c) सही नहीं है।
- राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देगा। वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है। और न संसद के पास पुनर्विचार के लिये भेज सकता है। अत: विकल्प (d) सही है।
- विधेयक का दोनों सदनों से अलग-अलग पारित होना आवश्यक है। सदनों के बीच असहमति होने पर संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

2. यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक 'मूल संरचना' अथवा 'आकृति' है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है?
   (a) शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
   (b) गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
   (c) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973)
   (d) मिनेरवा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

उत्तर: (c)

व्याख्या: अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति संबंधी विवाद निम्न हैं:

- शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन द्वारा भाग-3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अंतर्गत नहीं आती।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले को उलट दिया और अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती है तथा अनुच्छेद 13(2) में 'विधि' शब्द में सभी विधियाँ शामिल हैं।
- 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ मामले के निर्णय को समाप्त कर दिया गया और माना गया कि ससंद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि में शामिल नहीं होगी।
- केशवनानंद भारती (1973) मामले में 24वें संविधान संशोधन को वैध माना तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियाँ अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं हैं तथा 'संविधान के मूल ढाँचे का सिद्धांत' घोषित किया। अत: कथन (c) सही है।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) निर्णय में निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और इस अधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. यद्यपि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी परिवर्तन से संविधान में बदलाव हो जाता है, परन्तु यह बदलाव संसद द्वारा साधारण कानून बनाकर किया जाता है, जो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है।
   2. संविधान को साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और कम-से-कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन वाले विशेष प्रावधानों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

   उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न ही 1 और न ही 2

24 भारतीय संविधान : सामान्य पहलू (Indian Constitution : General Aspects)

1. भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है?
   (a) जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध
   (b) राज्यसभा में सीटों का आबंटन
   (c) संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची
   (d) भारत के संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएँ

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख हैं जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं-

प्रथम- राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र।

दूसरी- संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तें एवं पेंशन।

तीसरी- विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान।

चौथी- राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के लिये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अत: विकल्प (b) सही है।

पाँचवी- अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण।

छठी- असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध।

सातवीं- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय।

आठवीं- संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ।

नौवीं- भूमि सुधार।

दसवीं- दल-बदल के आधार पर निरर्हताएँ।

ग्यारहवीं- पंचायतों की शक्तियों व ज़िम्मेदारियाँ।

बारहवीं- नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व ज़िम्मेदारियाँ।

2. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं?
   1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
   2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
   3. पंचम अनुसूची
   4. षष्ठ अनुसूची
   5. सप्तम अनुसूची

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 3, 4 और 5
   (c) केवल 1, 2 और 5
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

व्याख्या: राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व: अनुच्छेद 45 (राज्य छ: वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के प्रारंभिक बाल्यकाल की देख-रेख और शिक्षा का प्रयास करेगा)

- **ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय:** अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकाय (11वीं अनुसूची विषय संख्या 17, 18 एवं 19) तथा अनुच्छेद 243ब (12वीं अनुसूची विषय संख्या 13) द्वारा शहरी स्थानीय निकाय में शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- **पाँचवी अनुसूची:** पाँचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किये गए हैं। पाँचवी अनुसूची में स्पष्टत: शिक्षा की बात तो नहीं की गई है परंतु इस अनुसूची में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं।
- **छठी अनुसूची:** छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किये गए हैं। छठी अनुसूची में स्पष्टत: उल्लेख है राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में किसी भी समय जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये एक आयोग नियुक्त कर सकता है जो शिक्षा, चिकित्सा, संचार के संबंध, नवीन कानून की आवश्यकता (विधि, नियमों, विनियमों) के संबंध में जाँच कर सकता है।
- **सातवीं अनुसूची:** सातवीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।

3. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

प्रावधान		**अनुसूची**
1. दल-परिवर्तन रोधी कानून	–	बारहवीं अनुसूची
2. शपथ या प्रतिज्ञान	–	दूसरी अनुसूची
3. संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ	–	दसवीं अनुसूची
4. भूमि सुधार	–	छठीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारतीय संविधान में 12 अलग-अलग अनुसूचियाँ दी गई हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, प्रश्नानुसार सही सुमेलन निम्न प्रकार से हैं-

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

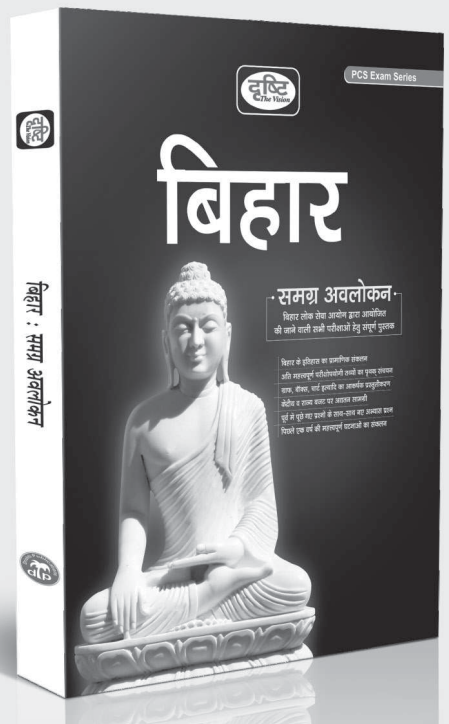

दृष्टि पब्लिकेशन्स

की शानदार प्रस्तुति

प्रमुख आकर्षण

- बिहार के इतिहास का प्रामाणिक संकलन
- अति महत्त्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों का पृथक् संचयन
- ग्राफ, बॉक्स, चार्ट इत्यादि का आकर्षक प्रस्तुतीकरण
- केंद्रीय व राज्य बजट पर अद्यतन सामग्री
- पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ नए अभ्यास प्रश्न
- पिछले एक वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संकलन

दृष्टि पब्लिकेशन्स

की शानदार प्रस्तुति

बी.पी.एस.सी.

मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन

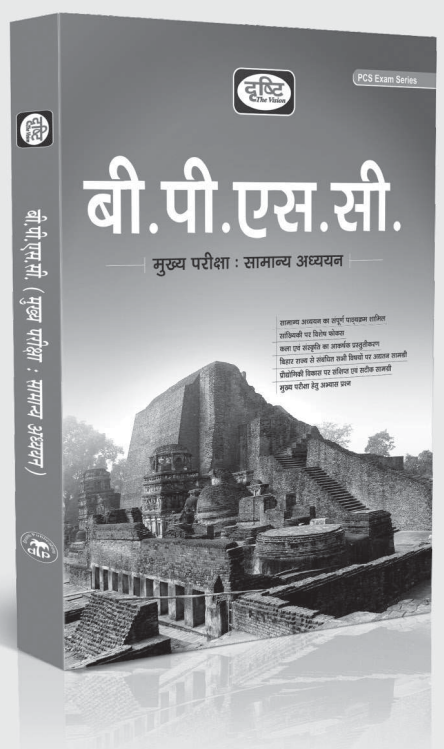

प्रमुख आकर्षण

- सामान्य अध्ययन के संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेशन
- सांख्यिकी पर विशेष फोकस
- कला एवं संस्कृति का आकर्षक प्रस्तुतीकरण
- बिहार राज्य से संबंधित सभी विषयों पर अद्यतन सामग्री
- प्रौद्योगिकी विकास पर संक्षिप्त एवं सटीक सामग्री
- मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

(IAS व PCS प्रिलिम्स परीक्षा पर केंद्रित शृंखला)

1

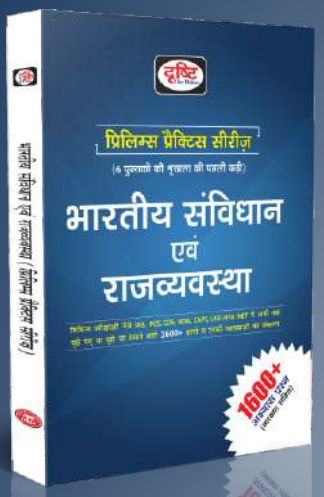

2

3

4

5

6

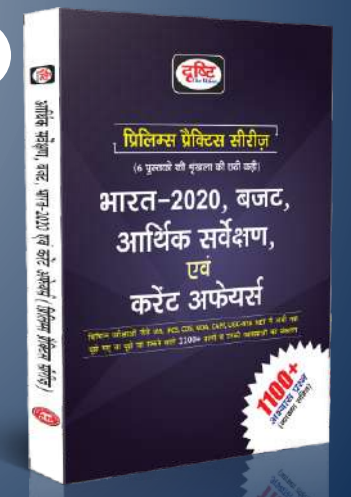

Drishti Publications

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-945304-2-8

मूल्य : ₹ 280